सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

अनमोल विचार

यदि मेरी सफलता की परीभाषा मजबूत है तो असफलता कभी मुझसे आगे नहीं जा सकती।

-डा. अब्दुल कलाम

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • EDITOR: ATUL SHARMA • 17 SEPTEMBER TO 23 SEPTEMBER 2019 • VOLUME-7 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • Mobile: 99881-15514 • email:atul_editor@jalandharbreeze.com

पुडा विभाग

मुख्यमंत्री पंजाब को जल्द से जल्द इस नियम को हटाकर नई नोटिफकेश्न जारी कर के लोगों को इस संकट से उभारने की जरूरत है और जिस कदर अफसर शाही कारोबारी नक्शों की मंजूरी और बहुमत तबदीली के केसों को उलझा रहे है इससे आम जनता तो पीड़ित है और सरकार को बड़े स्तर पर राजस्व का नुकसान हो रहा है।

सरकार की गलत नीतियों के कारण रीयल स्टेट के करोडों रुपये के प्रोजैक्ट पास नहीं हो रहे

■ जालंधर से नीरज की विशेष रिपोर्ट

पूरे पंजाब में रियल स्टेट कारोबार बड़े स्तर पर मंदी की मार झेल रहा है। दूसरी तरफ पंजाब की सरकार कारोबारियों की मदद करने की बजाए उनको ओर उलझा रही है जिसका प्रमुख कारण पंजाब सरकार में एसी बंद कमरों में बैठे अफसर जो गलत नीतियां बना के सरकार की छवि को ठेस पहुँचा रही है। जिस का एक उदाहरण पंजाब सरकार द्वारा सीएलयू करवाने के लिए जारी नोटिफकेशन मीमो नं 18/02/19-5 मउ 1414558 तिथि, चंडीगढ़ 8/2/2019, पंजाब सरकार के मकान उसारी और शहरी विकास विभाग के डरैक्टर द्वारा एक नोटिफकेशन जारी की गई थी जिस नोटिफकेशन में बताया गया कि 31/12/18 तक सीएलयू के केसों को विभाग के सभी दफ्तरों के पास जो लंबित केस चले आ रहे है उससे पुरानी प्रथा अनुसार संबंध सर्कल रैवीन्यु अफसर से कब्जा तसदीक करवाते हुए उसे मंजूर किया जाए और बिनेकार से हलफीया ब्यान लिया जाये कि अगर भविष्य में किसी को-शेयरर के साथ झगड़ा होता है उसका संबंधित विभाग जिम्मेवार नहीं होगा, परन्तु 1/1/2019 के बाद विभाग के सभी दफ्तरों में प्राप्त हुए केसों को डील करते समय प्रार्थी से उसकी निजी मलकीयत, या उसकी पार्टीशन, या बची हिस्सेदारी के मालिकों से सहमती ली जाए।

इस नोटिफकेश्न से रियल स्टेट कारोबारियों और आम इंसान की कारोबारी जमीन को खत्म किया जा रहा है अगर सरकार का मकसद

हकीकत में ही सिस्टम को दरुस्त करना है ताकि सांझे खाते के केसों में पुडा विभाग को अदालतों के चक्करों में ना पड़ना पड़े तो इनकी रजिस्टरी के टाईम पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि अगर किसी ने धोखे से सांझे खाते में से दूसरे साझेदारों खाते में बचे मालिकों को बिना बताए अगर किसी तरह की जमीन की खरीद फरोखत की जाती है तो उस पर रोक लग सके ताकि भविष्य में उस मालिक को जिस ने लाखों की स्टाप ड्यूटी भर कर अपने नाम करवाया है अपने आप को ठगा महसूस ना करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है पंजाब के बड़े स्तर पर लोग विदेश में रहते है ओर सीएलयू करवाने के लिए उसे सहमती प्राप्त करना या जमीन को पाटीशन के लिए उनको बुलाना बहुत ही कठिन ओर असंभव काम है।

इस लिए सरकार को यह नोटिफकेशन जारी करना चाहिए कि कोई भी राजिस्टरी भविष्य में सांझेदार खाते की मालिकों को एक-दूसरे की सहमती के बगैर खरीदी यां बेची नहीं जा सकती ताकि राजिस्टरी होने के बाद किसी भी इंसान को लाखों रुपए जमीन के सौदों पर खर्च के और लाखों रूपए विभाग के राजस्व के रूप मे जमा करवा के अपने आप को ठगा महसूस ना करे और जैसेकि विभाग द्वारा 31/12/18 के जमा हुए केसों को पुरानी प्रथा के अनुसार ही मंजूर करने का हुक्म हुआ है।

उसी अनुसार जब तक राजिस्टरी पर रोक नहीं लगती लोगों के विभाग के पास जमा हुए और हो रहे केसों को पुरानी प्रथा के अनुसार ही मंजूर किया जाये क्योंकि पंजाब वैसे ही बड़े गहरे वित्तीय संकट से गुजर रहा है और आम इंसान इस मंदी के कारण बैंकों से लिए कर्जे के नीचे दब रहा है। मुख्यमंत्री पंजाब को जल्द से जल्द इस नियम को हटाकर नई नोटिफकेश्न जारी कर के लोगों को इस संकट से उभारने की जरूरत है और जिस कदर अफसरशाही कारोबारी नक्शों की मंजूरी और बहुमत तबदीली के केसों को उलझा रहे है इससे आम जनता तो पीड़ित है और सरकार को बड़े स्तर पर राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसलिए इन अफसरों को जल्द से जल्द ठोस निर्देश जारी होने चाहिए ताकि इस प्रणाली को सरल बनाने के लिए अफसर काम करें ओर लोगों को सहूलियत प्रदान की जा सके।

मीडिया की स्वतंत्रता पर सुप्रीम सुनवाई

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने, कल्याणकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने, स्कूल और कॉलेज खोले जाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट निपट सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा कि इन हलफनामों का विवरण दें और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रयास किए जाएं। केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि कश्मीर संभाग के 88 प्रतिशत से अधिक थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। एक गोली भी नहीं चलाई गई और कुछ स्थानीय प्रतिबंध लगे हैं। दूरदर्शन जैसे टीवी चैनल और अन्य निजी चैनल, एफएम नेटवर्क काम कर रहे हैं। प्रतिबंधित इलाकों में पहुंच के लिए मीडिया को 'पास' दिए गए हैं और पत्रकारों को फोन और इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। कश्मीर स्थित सभी समाचार पत्र चल रहे हैं और सरकार हरसंभव मदद मुहैया करा रही है। बता दें कि पत्रकार अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि घाटी में अभी ना इंटरनेट है, ना ही संचार माध्यम की कोई सुविधा है। जिस पर आज सुनवाई हुई।

राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सरकार-गोगोई

जन्मदिन पर बोले चिदंबरम, ईश्वर इस देश की रक्षा करे

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम सोमवार को 74 साल के हो गए और इस मौके पर उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि ईश्वर इस देश की रक्षा करे। चिदंबरम के परिवार ने उनकी तरफ से उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर टिप्पणी पोस्ट की है। इसमें चिदंबरम ने कहा, मेरे परिवार ने मेरे मित्रों, पार्टी सहयोगियों और शुभचिंतकों की तरफ से मुझ तक शुभकामनाएं पहुंचाई हैं।

मुझे याद दिलाया गया कि मैं 74 साल का हो चुका हूं। मैं 74 का हूँ लेकिन दिल से मैं खुद को 74 साल का नौजवान महसूस करता हूं। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सभी का धन्यवाद। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, मैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहा हूं । सिर्फ एक आंकड़ा पूरी कहानी बयां करता है। अगस्त महीने में निर्यात वृद्धि में 6.05 फीसदी की गिरावट रही। निर्यात में 20 फीसदी की वृद्धि के बिना कोई देश आठ फीसदी की जीडीपी वृद्धि दर तक नहीं पहुंच सकता।

उन्होंने कहा, ईश्वर इस देश की रक्षा करे। चिदंबरम के जन्मदिन के मौके पर उनके पुत्र कार्ति ने उन्हें भावनात्मक रूप से याद किया तो जयराम रमेश समेत कई कांग्रेस नेताओं ने चिदंबरम को जन्मदिन की

बधाई दी।कांग्रेस सांसद कार्ति ने अपने पिता को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि कोई 56 इंच आपको नहीं रोक सकता।

कार्ति ने अपने पिता के नाम लिखे पत्र में कहा, आज आप 74 साल के हो गए लेकिन कोई 56 इंच आपको रोक नहीं सकता। आप कभी भी अपने जन्मदिन को भव्य अंदाज में नहीं मनाते, लेकिन इन दिनों हमारे देश में हर छोटी बात पर बड़ा जश्न होने लगा है। कार्ति ने आगे लिखा, बिना आपके यह जन्मदिन पहले जैसा नहीं होगा। हम आपकी कमी महसूस कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का जश्न मना रही है और ऐसे में आपकी आवाज दबाने का यही सही समय था। आप उनसे असहमत होकर उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ विरोध करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, चिदंबरम आज 74 साल के हो गए। वह अग्निपरीक्षा

शेष पृष्ठ 2 पर »

5 साल और 100 दिन में कितनी नौकरियां दीं ?-प्रियंका

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के ताजा बयान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल किया कि पिछले पांच वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तर भारत के लोगों को कितनी नौकरियां दी हैं। गंगवार के बयान से जुड़ा वीडियो पोस्ट करते हुए प्रियंका ने अपने ट्वीट में कहा,'' मंत्री जी, आपने इतनी बड़ी बात बोली है तो अब आँकड़े भी दे

दीजिए। आपने कितनी नौकरियाँ पिछले 5 साल और 100 दिन में दीं। पिछले 5 वर्षों में कितने उत्तर भारतीयों को नौकरियाँ दीं? स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत कितनी नौकरियाँ दीं?'' उन्होंने कहा, ''याद रखिए, नौकरियाँ छीनने के आँकड़े जनता के पास हैं।'' गौरतलब है कि गत शनिवार को गंगवार ने कहा कि देश में रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है लेकिन उत्तर भारत में आने वाले नियोक्ताओं की शिकायत है कि रिक्तियां भरने के लिये योग्य लोगों

शेष पृष्ठ 2 पर »

वार्ड में काम करवाना है तो क्या सत्ताधारी पार्टी का पार्षद जितवाना जरूरी ?

■ जालंधर से नीरज की विशेष रिपोर्ट

आज के दौर की राजनीति नये रूप की ओर जा रही है जिस में चुने हुए लोगों द्वारा अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने के बाद चुना हुआ नुमाइदां सत्ताधारी पार्टी द्वारा नकारा जा रहा है इस का एक उदाहरण वार्ड नं 66 गोपाल नगर में आजाद पार्षद का जीतना सत्ताधारी पार्टी को रास नहीं आ रहा। इस का मुख्य कारण गोपाल नगर में हर विकास कार्य को रोकना चाहे वो सड़क निर्माण, पानी की समस्या के लिए ट्यबूल का लगना, बिजली की पूर्ति के लिए नये ट्रांसफार्मर का लगना, गंदे पानी की रोकथाम के लिए कदम उठाने ओर अनेकों ऐसे मुद्दे जो पार्षद के स्तर पर दूर करवाए जाते है वो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के विधायक द्वारा इसे रुकवाना लोगों के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा क्योंकि पार्षद चुनाव बहुत ही कम गिनती की वोटों का होता है और लोगों द्वारा हमेशा उसी शख्स को चुना जाता है जिस की छवि लोगों

के बीच में पारिवारिक हो ओर हर छोटी से बड़ी समस्या के बारे में लोग उसके पास पहुँच सके। पर मौजूदा राजनीति वार्ड नं. 66 के गलियारों में गलत संदेश दे रही है और लोगों के मन में विधायक के प्रति काफी रोष पनपा हुआ है इसलिए विधायक को राजनीति से ऊपर उठ के लोगों के डिवैल्पमैंट के कामों को आगे होकर एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि वो दूसरे राजनीतिज्ञों की तरह छोटी सोच नहीं रखते ओर जनता के कामों के लिए किसी भी अफसर को भेदभाव या राजनीति से प्रेरित हो के किसी भी वार्ड के डिवैल्पमैंट के कामों को रोकने की इजाजत नहीं देगें। जनता सब जानती है कि विधायक का काम क्या होता है, पार्षद का काम क्या होता है इसलिए हमें इस बात की चिंता छोड़ देनी चाहिए कि अगर पार्षद के काम हो जाते है तो इसका क्रैडिट उसको मिलेगा। क्योंकि पार्षद चुनाव और विधायकी के चुनावों में काफी अंतर है।

लेबर विभाग

भारत में बाल मजदूरी कूड़े से भी बड़ी गंदगी

बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल न किसी बात की चिंता और न ही कोई जिम्मेवारी। बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना कूदना और पढ़ना। लेकिन बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो और वह जीविका के लिए काम करके बाल मजदूर कहलाता है। गरीब बच्चे बाल मजदूरी के इस दलदल में धंसते चले जाते है। इन बच्चों का समय स्कूल में कॉपी किताबों और दोस्तों के बीच नहीं बल्कि होटलों, घरों में उदय होता है। भारत में यह स्थिति बहुत ही भयानक हो चली है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में है। बड़े शहरों के साथ-साथ आपको छोटे शहरों में भी हर गली नुक्कड़ पर कई छोटू मिल जाएंगे जो हालातों के चलते बाल मजदूरी की गिरफ्त में आ चुके है। इसके साथ ही बच्चों को कई घिनौने कुकृत्यों का भी सामना करना पड़ता है। जिनका बच्चों के मासूम मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। कई एनजीओ समाज में फैली इस कुरीतियों को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास कर रहे है। इन एन.जी.ओ के अनुसार बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे है जो सप्ताह के सातों दिन काम करते है इसमें से हर दूसरे बच्चे को किसी न किसी तरह भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़े स्तर पर बच्चे शरीरिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे है। बाल मजदूर की इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया जिसके तहत बाल मजदूरी

को एक अपराध माना गया तथा रोजगार पाने की न्यूनतम चाइल्ड लेबर एक्ट के रूप में बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। इस प्रोजेक्ट का उदेश्य बच्चों को इस संकट से बचाना है। आज सरकार ने आठवीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और नि:शुल्क कर दिया है, लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे यह योजना भी निष्फल साबित होती दिखाई दे रही है। कई तो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते क्योंकि उनके स्कूल जाने से परिवार की आमदनी कम हो जाएगी। माना जा रहा है कि आज बड़ी संख्या में बच्चे बाल मजदूरी के शिकार है, अगर इसके आज मौजूदा आकड़े निकाले जाए तो सरकार को अपनी आंखे खोलनी होगी। यहां एक तरफ तो ऐसे बच्चों का समूह है जो बड़े-बडे मंहगे होटलों में 56 भोग का आनंद ले रहै है ओर दूसरी तरफ जो गरीब है, अनाथ है, जिन्हें पेटभर खाना भी नसीब नहीं होता। दूसरों की जूठनों के सहारे वे अपना जीवन व्यतीत करते है।

आखिर ये बच्चे क्या करें कहां जाएं ताकि इसकी समस्या के खिलाफ कानून तो बना दिए। इसे एक अपराध भी घोषित कर दिया लेकिन क्या बच्चों की कभी गंभीरता से सुध ली? बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है गरीबी को खत्म करना।

इस बच्चों के लिए दो वक्त का खाना मुहैया कराना। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हर व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम हो अगर ऐसे एक बच्चे की भी जिम्मेवारी लेने लगे तो सारा समाज ही बदल जाएगा। इसका एक उदाहरण कैलाश सत्यार्थी नोबल पुरस्कार विजेता द्वारा किए जा रहे देश भर में प्रशंसनीय योग काम जो बड़े स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए बड़े साहसिक कदम उठा रहे है क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह नर्क में जाने से आप भी कैलाश सत्यार्थी का रूप धारण कर सकते है?

देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी जाहीए। जो इस कुर्सी में बैठे अफसरों के ऊपर आगे हो कर कार्रवाई करवानी चाहिए जो इसकी रोकथाम करने में अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा नहीं रहे।

ट्विटर

ईरान ने दुनिया भर में तेल सप्लाई रोकने के लिए ड्रोन हमले करवाए हैं। ईरान से सुलह की कोशिश अमेरिका कर रहा है, मगर इस तरह कोशिशें अधूरी ही रहेंगी।

-माइक पोम्पियो, विदेश मंत्री अमेरिका

उक्ति

"अधिक अनुभव, अधिक सहनशीलता और अधिक अध्ययन यही विद्वत्ता के तीन महास्तंभ हैं। इन तीनों के जरिए कुछ भी हासिल किया जा सकता है।

-चाणक्य

दखल

तालिबान से आगे अब क्या

अफगानिस्तान में तालिबानों के वर्चस्व का मतलब पाकिस्तान का परोक्ष आधिपत्य। भारत इसी का तोड़ निकालने में जुटा है। तालिबान से वार्ता के बावजूद वहां हिंसक गतिविधियां जारी रहीं। लिहाजा, ट्रंप बातचीत के दौर से बाहर आए गए। अब देखना होगा कि अमेरिका आगे क्या करता है। लेकिन तत्काल भारत और पूरे क्षेत्र के लिए यह राहत की खबर है। हमारा लक्ष्य तालिबान को परास्त करने का है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर देंगे या बोल देंगे इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी जोखिम भरी होगी। बावजूद इसके तालिबान से बातचीत को खत्म करने की उनकी घोषणा वाकई राहतकारी है। जब पिछले दो अगस्त को घोषणा हुई कि अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है तो पूरी दुनिया में भविष्य को लेकर कई प्रकार की आशंकाओं के स्वर उभरने लगे। उस घोषणा के अनुसार अमेरिका नाटो सहित अपनी फौजों को वापस कर लेगा। ट्रंप प्रशासन के अंदर इस बात पर सहमति है कि हमें किसी तरह अफगानिस्तान से निकल भागना है। इसीलिए जल्मे खलीलजाद को विशेष प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया एवं वो पिछले दिसंबर से कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के साथ नौ दौर की बातचीत के बाद समझौते के एक मसौदे पर पहुंचे थे। साफ लगने लगा था कि अमेरिका और तालिबान इस पर हस्ताक्षर करने ही वाले हैं। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने घोषणा की कि वे इस समझौते से सहमत नहीं हैं। हालांकि तब भी विशेषज्ञ यह मान रहे थे कि ट्रंप विदेशमंत्री को दरकिनार कर स्वयं हस्ताक्षर कर देंगे। तत्काल ट्रंप ने वही किया जो उनके विदेश मंत्री चाहते थे। प्रश्न है कि अब आगे क्या?

इस बारे में कुछ भी कहना कठिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ वार्ता से पीछे हटने की वजह पांच सितंबर को काबुल में तालिबान द्वारा किया गया है हमला बताया है जिसमें एक अमेरिकी सैनिक समेत 12 लोग मारे गए। माइकपौम्पियो ने कहा है कि अगर तालिबान रवैया बदले तो वार्ता फिर हो सकती है। यह वार्ता तालिबान के लिए कितना अनुकूल था इसका पता ट्रंप के निर्णय के बाद आए उसके बयान से चलता है। तालिबान ने कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान वॉशिंगटन को होगा लेकिन वह भावी वार्ता के लिए द्वार खुला छोड़ता है। तालिबान की ओर से ट्विटर पर जारी बयान में प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम अब भी....विश्वास करते हैं कि अमेरिकी पक्ष को यह समझ में आएगा...पिछले 18 सालों से हमारी लड़ाई ने अमेरिकियों के लिए साबित कर दिया है कि जब तक हम उनके कब्जे का पूर्ण समापन नहीं देख लेते तब तक संतुष्ट नहीं बैठेंगे। इस बयान का अर्थ तो यही है कि तालिबान अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा था। उसका मानना है अमेरिका उसको पराजित नहीं कर सकता, इसलिए हारकर समझौता वार्ता करने आया। इसमें धमकी भी है कि हम अमेरिका के कब्जे को पूरी तरह खत्म कर देंगे। नौ दौर की वार्ता के बाद भी यदि तालिबान में इतना दंभ है तो फिर इससे समझा जा सकता है खलीलजाद साहब किस शैली में वार्ता कर रहे थे। भारत ने हमेशा इस वार्ता का विरोध किया था।

भारत का मानना था कि इससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अफगानिस्तान के शासन पर कब्जा के लिए संघर्ष करेंगे। उनकी आज जैसी ताकत है उसमें वे गठबंधन सेनाओं की वापसी के बाद कब्जा करके फिर मन का इस्लामी शासन लागू करेंगे जिसमें खड़ा किया गया आधुनिक ढांचा ध्वस्त कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के लोकतंत्र स्थापना में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके चुनाव में हमारे चुनाव आयोग और पर्यवेक्षक तक लगे। उसका संसद भवन भारत ने बनाया। इसी तरह शिक्षा और स्वास्थ्य के कई केंद्र भारत ने बनाए। तालिबान के लिए ये सब इस्लामी विचारधारा के विरुद्ध है। तो वे इसे बनाए क्योंकर रखेंगे? इस बीच जो शिक्षालय वहां अस्तित्व में आए हैं, मीडिया विकसित हुई है, फिल्में बन रहीं हैं, थियेटर भी शुरू हुए हैं, युवक-युवतियां खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे हैं। तालिबान इन सबको खत्म करेगा यह निश्चित है।

सच यही है कि अमेरिका भले तालिबान से वार्ता करता रहा लेकिन उनकी हिंसा जारी रही। तालिबान ने समझौता पर सहमति की घोषणा के बाद 7 सितंबर को कुंदूज शहर पर कब्जे का प्रयास किया था। इसके अगले दिन उसके आतंकवादियों ने बगलान प्रांत की राजधानी पुल-ए-खुमरी पर धावा बोला था। कुंदूज और अन्य उत्तरी इलाकों में हिंसा जारी है। कुंदूज में पुलिस चेकपोस्ट पर आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में दो पुलिस अधिकारी मारे गए और सात घायल हुए। आम धारणा यही है कि 18 सालों में तालिबान इस समय सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अमेरिकी नेतृत्व में गठबंधन सेना की लगातार कारवाई के बावजूद तालिबान का अफगानिस्तान के आधे भूभाग पर कब्जा कायम है। इसमें आसानी से समझा जा सकता है कि अफगानिस्तान में मौजूद करीब 20 हजार नाटो सैनिकों के हटने के बाद वहां के हालात क्या होंगे।

हालांकि अफगानिस्तान सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर दिया था। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बयान दिया कि बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले समूह से शांति समझौता करना निरर्थक है। यह कितनी अजीब वार्ता थी इसका अंदाजा इसी से चल जाता है कि इसमें अफगानिस्तान की सरकार शामिल ही नहीं थी। तालिबान ने अमेरिका के सामने शर्त रखी थी कि सरकार से हम वार्ता नहीं करेंगे। अमेरिका ने इस शर्त को मान लिया तो यह तालिबान का मनोबल बढ़ाने वाला ही साबित हुआ। मसौदे के बारे में जितना कुछ बाहर आया है उसे समझने की कोशिश करें। खलीलजाद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि समझौते के बाद अमेरिका 135 दिनों में अफगानिस्तान से अपने 5,400 से ज्यादा सैनिकों को हटाएगा। फिर 14 से 24 माह में अफगानिस्तान से सारे अमेरिकी सैनिक जिनकी संख्या 14 हजार हैं, हटा दिए जाएंगे। तालिबान ने अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से दूर रहने का वादा किया है। तालिबान अफगानिस्तान को फिर से आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनने देगा। सत्ता साझा करने के मसले पर तालिबान अफगान सरकार के साथ वार्ता करेगा। खलीलजाद ने यह भी कहा था कि इससे हिंसा में कमी आएगी और स्थायी शांति का रास्ता खुलेगा। जरा सोचिए, एक आतंकी संगठन अफगानिस्तान को आंतकवाद का अड्डा नहीं बनने देगा और अल कायदा से दूर रहेगा यह संभव है क्या? जो संगठन अफगानिस्तान सरकार को वार्ता तक में शामिल होने देने के लिए तैयार नहीं वह सत्ता साझा करने के लिए उससे बात करेगा? इसे ही कहते हैं मूर्खों के स्वर्ग में रहना।

अमेरिका भागने की जल्दबाजी में सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ रहा था। पाक द्वारा तालिबान को संरक्षण देने को लेकर वे बयान दे रहे थे। पर अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रति अपना व्यवहार अचानक बदल दिया था। उसे लगता था कि पाक इसमें भूमिका निभा सकता है। भारतीय कूटनीति भी सक्रिय थी। जब रूस ने आईएसआईएस को अफगानिस्तान से बाहर रखने के नाम पर तालिबान से अनौपचारिक बातचीत की तो उन्होंने भारत को बुलाया। भारत के प्रतिनिधि गए पर वार्ता से अलग रहे। दरअसल, भारत की समस्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों हैं। अफगानिस्तान में तालिबानों के वर्चस्व का मतलब पाकिस्तान का परोक्ष आधिपत्य। हालांकि, अफगानिस्तान से वापसी ट्रंप का चुनावी वादा है। वो हर हाल में वहां से निकलने चाहते थे। अब देखना होगा कि अमेरिका आगे क्या करता है। लेकिन तत्काल भारत और पूरे क्षेत्र के लिए यह राहत की खबर है। हमारा लक्ष्य तालिबान को परास्त करने का है।

■ अवधेश कुमार
(वरिष्ठ पत्रकार)

विशेष संपादकीय

इमरान का शांति का रोना ढोंग

सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट अरामको की दो तेल रिफाइनरियों पर हुए ड्रोन हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर गहरा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक ईरान से बातचीत किए जाने को तैयार थे, अब बिफर गए हैं। ट्रंप की तरफ से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि सऊदी अरब पर लगभग 100 हमलों के लिए तेहरान जिम्मेदार है जबकि रूहानी और जरीफ कूटनीति में शामिल होने का दिखावा करते हैं। ईरान ने अब दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर एक अभूतपूर्व हमला किया है। यमन के हमलों का कोई सबूत नहीं है। बता दें कि ड्रोन हमले के कारण रियाद से 150 किलोमीटर दूर अबकैक शहर में रिफाइनरी में आग लग गई। अरामको कंपनी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट के रूप में जानी जाती है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ईरान ने दुनिया भर में तेल सप्लाई रोकने के लिए ड्रोन हमले करवाए हैं। शनिवार के इस हमले से सऊदी अरब में तेल सप्लाई पर काफी असर पड़ा है और तेल की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। मध्य पूर्व के कई देशों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। यमन के ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों ने ऑयल रिफाइनरी पर हमले की जिम्मेदारी ली है। विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया जिसमें 10 ड्रोन शामिल थे, जिन्होंने पूर्वी अरब में अबकीक और खुरेस में रिफाइनरियों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ने की आशंका प्रबल हो गई है क्योंकि एटमी डील को लेकर अमेरिका और ईरान पहले से एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। अरामको का खुरेस ह्श्वलांट हर दिन लगभग 10 लाख बैरल कच्चा तेल प्रोसेस करता है। अरामको के मुताबिक, इस प्लांट के पास फिलहाल 20 अरब बैरल तेल रिजर्व है। यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के हालात हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पैदा हुए तनाव को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। फिक्र की बात ये है कि दोनों ही तरफ परमाणु ताकत से लैस देशों की खेमेबंदी है। ऐसे में जरा सी चूक एक भयानक जंग को जन्म दे सकती है। अमेरिका ईरान को सबक सिखाने की धमकी दे चुका है, वहीं रूस ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला बोलता है तो अंजाम खौफनाक होगा क्योंकि वो चुप नहीं बैठेगा। हालात उस समय और बिगड़ना शुरू हुए जब पिछले महीने के मध्य में ओमान की खाड़ी में दो तेल टैंकरों में धमाके हुए जिसका आरोप ईरान पर लगाने में अमेरिका ने कोई देरी नहीं की। इसके बाद ईरान ने अमेरिका के शक्तिशाली आरक्यू-4 ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया। अब ताजा मामला अरामको का है। हमले की जिम्मेदारी भले ही हूती विद्रोहियों ने ली हो, मगर अमेरिका इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने की हर संभव कोशिश करने में जुट गया है।

दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए

भगवा और हरा, महज दो रंग ही नहीं हैं। हमारे यहां यह दो धर्म और आस्थाओं के प्रतीक हैं। जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात इन दोनों रंगों को मिलाकर खुशरंग बनाने में कितनी कारगर होगी? फिलहाल इस संबंध में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अलबत्ता बातचीत के दौरान कुछ मुद्दों पर ही सही एकराय बनना और आगे भी मुलाकातों के सिलसिले को जारी रखने पर सहमति बनने की एक आस तो बंधती ही है। मुलाकात का समय महज आधा घंटे तय का था लेकिन बात जब निकली तो दूर तलक गई। आपसी गिले-शिकवे भी दूर होने लगे और बातचीत का सिलसिला तय समय सीमा से बढ़कर डेढ़ घंटे तक खिंच गया। इसे एक-दूसरे के संबंधों पर बरसों से जमी बर्फ पिघलने के आसार के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल, आरएसएस इस मुलाकात को लेकर ज्यादा कुछ कहने से बचता रहा है। उसके अनुसार संघ गाहे-बगाहे दूसरे समुदाय और तबकों के नेताओं से मुलाकात करता रहता है। यह भेंटवार्ता इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन जमीअत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस मुलाकात और बातचीत का कुछ ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। हालांकि बाद में वह भी इस पर ज्यादा कुछ कहने से बचते नजर आए। नेक पहल होने के बावजूद अचानक इसकी पर्दादारी से लोगों में थोड़ा संशय जरूर पैदा हुआ है लेकिन दोनों तरफ के अधिकतर लोग इसे लेकर अब भी आशावान हैं। बातचीत मुख्यत: मॉब लिंचिंग, बढ़ते वैमनस्व और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के इर्दगिर्द रही। मौलाना मदनी के अनुसार मोहन भागवत ने उनकी इस बात से सहमति जताई कि आज देश में धार्मिक उन्माद की वही स्थिति है जो आजादी से पहले थी। उससे मुल्क का बंटवारा हुआ। स्वतंत्रता पूर्व मजहबी नफरत के लिए मुसलमान जिम्मेदार थे तो आज बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता वैसा वैमनस्व फैला रहे हैं। इसे रोके जाने की आवश्यकता है। मौलाना का दावा है कि उन्होंने सरसंघचालक मोहन भागवत से वीर दामोदर सावरकर और माधव सदाशिव गोलवलकर समेत संघ की मूल 'हिंदुत्व' वाली विचारधारा पर भी अपना विरोध जताया। इसपर मोहन भागवत ने न केवल इसे दरकिनार कर आगे वार्ता के लिए किसी बिंदु पर सहमति बनाने की बात कही बल्कि हिंदुत्व की व्याख्या हिंदुओं और मुसलमानों के एकसाथ मिलजुल कर काम करने के तौर पर की। उन्होंने कहा कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसमें हिंदू-मुस्लिम समेत दीगर धर्मों के लोग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि सितंबर 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में 'भविष्य का भारत' विषय पर आयोजित संघ के तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम में भी मोहन भागवत ने कहा था कि गुरु गोलवलकर द्वारा लिखी किताब 'बंच ऑफ थॉट्स' की तमाम बातों को शाश्वत नहीं माना जा सकता। वह परिस्थितिवश लिखी गई थी। मौलाना मदनी से मुलाकात के दौरान भी इस तथ्य से गुरेज करना उनके रवैये में लचीलेपन की दलील है। इससे अब देश के मुसलमानों को भी आरएसएस के प्रति अपने रुख में नरमी लाने की आवश्यकता है। यही क्या कम है कि दोनों रहनुमा 'हिंदू-मुस्लिम एकता के बिना देश का विकास असंभव' होने पर एकमत दिखाई दिए। इस पर मौलाना ने कहा कि यह बातें बंद कमरों में बैठ कर नहीं हो सकतीं। इसके लिए हमें खुले मैदान में आना होगा। फिर बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहने पर सहमति बनने से उम्मीद की जा रही है कि निकट भविष्य में दोनों संयुक्त रूप से एक प्लेटफार्म पर आकर कोई पैगाम दे सकते हैं। वैसे दोनों के एक मंच पर आने का एक मौका सितंबर-2018 के आरएसएस के संवाद कार्यक्रम में भी बना था लेकिन तब आम चुनावों और मॉब लिंचिंग की घटनाओं के कारण मौलाना मदनी ने यह सोचकर मना कर दिया कि कहीं इसके सियासी मतलब न निकाले जाएं। अब जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और अधिक प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज हुई तब मौलाना मदनी ने इस मुलाकात के लिए हामी भरी। इसके बावजूद दोनों की हालिया मुलाकात से संबंधित सियासी नफा-नुकसान तलाश किए जा रहे हैं और व्याख्याएं की जा रही हैं। कुछ लोग इसे नवंबर माह में अपेक्षित अयोध्या विवाद पर फैसले से जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि संघ इसको लेकर अपनी रणनीति अभी से तैयार करने में लगा है और यह मुलाकात भी इसी का हिस्सा है। कुछ लोगों का मानना है कि देश में आए दिन होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं में हिंदूवादी संगठनों की संलिप्तता के चलते ही उसकी छवि धूमिल हो रही है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त किए जाने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हर मंच से संघ को बदनाम करने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते। इसीलिए आरएसएस अपनी छवि सुधारने के लिए जमीअत के कंधों का सहारा ले रहा है। इसी तरह के कयासों के चलते ही दोनों संगठन इस मुलाकात के संबंध में मीडिया से कुछ कहने से बचने लगा। उन्हें लगने लगा कि इससे फायदा कम और नुकसान अधिक हो रहा है। खैर! 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना' लेकिन विचार तलब बात यह है कि हम किसी भी काम के शुरू में ही या तो बेहतर परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं या फिर मीन-मेख निकालने लगते है। इस मुलाकात को इन बातों से जोड़ने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों की मुलाकात का आधार उपरोक्त बातों से काफी पहले तय होने लगा था। दरअसल आरएसएस के कुछ लोग मौलाना अरशद मदनी और उनकी संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों से प्रभावित हुए। उनका आपस में मिलना-जुलना होने लगा। उन्होंने आरएसएस को लेकर मौलाना की आशंकाओं को जब मोहन भागवत के समाने रखा तो उन्होंने मुलाकात की इच्छा जताई। गत वर्ष के अपने संवाद कार्यक्रम में भी मौलाना को आमंत्रण देना इसकी नजीर है। गौरतलब है कि 2004 में भी तत्कालीन सरसंघचालक केएस सुदर्शन के समय में भी दोनों संगठनों के नेताओं की मुलाकात हुई थी। उससे पूर्व 1975 में आपातकाल के दौरान जेलों में बंद मुसलमानों के एक और प्रतिष्ठित संगठन जमात-ए-इस्लामी के नेताओं की आरएसएस नेताओं से मुलाकात हुई थी। इस बार की मुलाकात का महत्व इसलिए अधिक है कि इसमें आगे भी बातचीत जारी रखने पर जोर दिया गया है। किसी भी समस्या के हल के लिए यह जरूरी है कि आपसी बातचीत के दरवाजे कभी बंद न हों। दूरियां हमेशा आशंकाओं को बल देती हैं और इससे पहले से व्याप्त खाई और बढ़ती चली जाती है। इसके बरक्स मुलाकातें व बातचीत इसको पाटने का काम करती हैं। इसीलिए निदा फाजली ने कभी कहा था कि दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए।

जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच पिछले दिनों हुई मुलाकात मुख्यत: मॉब लिंचिंग, बढ़ते वैमनस्व और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के इर्दगिर्द रही। किसी भी समस्या के हल के लिए जरूरी है कि आपसी बातचीत के दरवाजे कभी बंद न हों। दूरियां हमेशा आशंकाओं को बल देती हैं।

सत्यार्थ संतों की जरूरत

एक दिन नामदेव से उनकी मां ने कहा- बेटा, जरा दवा बनाने के लिए आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी छाल उतार लाओ। मुझे एक जरूरी दवा बनाने के लिए उसकी जरूरत है। मां का आदेश मिलते ही नामदेव आंवले के वृक्ष की खोज में निकल पड़े। कुछ देर बाद जब वे आंवले के पेड़ की छाल उतार कर लौटने लगे तो रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिले। नामदेव ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने पूछानामदेव, यह क्या है? नामदेव ने कहा- दवा बनाने के लिए आंवले के वृक्ष की छाल उतार कर लाया हूं। महात्मा ने कहा- क्या तुम्हें पता नहीं कि हरे पेड़ को क्षति पहुंचाना अधर्म है। वृक्षों में भी तो जीवन होता है। इन्हें देवता मान कर पूजा जाता है। वैद्य जब किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़ते हैं, तो पहले हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करते हैं कि दूसरों के प्राण बचाने के उद्देश्य से ही आपको यह कष्ट दिया जा रहा है। यह हमारी संस्कृति का विधान है। नामदेव इस बात से बहुत प्रभावित हुए। घर जाकर उन्होंने छाल मां को दे दी और एक कमरे के कोने में बैठकर चाकू से अपने पैर की त्वचा छीलने लगे। उनके पैर से खून बहते देखा, तो मां ने पूछा-तू यह क्या कर रहा है? नामदेव बोले कि महात्मा ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है। मैं पैर की त्वचा उतारकर देख रहा हूं कि क्या त्वचा उतारने में दर्द होता है? यह सुनकर मां ने बेटे को छाती से लगा लिया। वे समझ गईं कि उनके बेटे पर सत्संग के विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। आगे चल कर तो नामदेव खुद ही संत बन गए। उन्होंने कण-कण में भगवान के दर्शन किए हैं। सचमुच, अब नामदेव जैसे संतों की ही जरूरत है, जो कि पर्यावरण का महत्व समझ सकें एवं दूसरों को भी समझाकर हरे-भरे वृक्षों को कटने से रोक सकें।

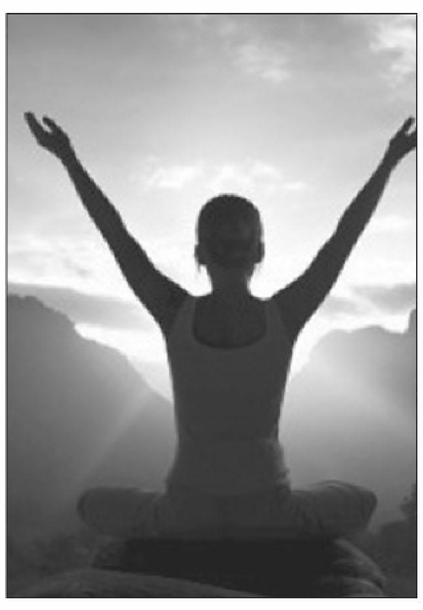

पृष्ठ 1 का शेष

जन्मदिन पर बोले चिदंबरम...

से गुजर रहे हैं लेकिन वह पाक साफ साबित होंगे। मैंने उनके साथ 1986 से काम किया है। मेरी प्रार्थना उनके साथ है। गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पी चिंदबरम को पिछले दिनों अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है जिस पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी।

z âëÜ ¥õÜ v®®...

की कमी है। गंगवार के इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने पलटवार किया। विपक्ष ने उन पर उत्तर भारत के लोगों के अपमान का आरोप लगाया।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी है

ओजोन

ओजोन परत सुरक्षित नहीं होने पर धरती पर क्या होगा प्रभाव?

ओजोन परत ओजोन अणुओं की एक परत है, जो विशेष रूप से 20 से 40 किमी के बीच के वायुमंडल के समताप मंडल परत में पाई जाती है। ओजोन परत वातावरण में बनती है, जब सूरज से पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन परमाणुओं को तोड़ती है। ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं और इस तरह ओजोन अणु बनाते हैं। समस्या जो इस परत की कमी से बनती है, वह यह है जब पृथ्वी की सतह पर चिपक जाने के बाद हानिकारक सूर्य के विकिरण वातावरण से निकलने में असमर्थ हो जाते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ओजोन परत के सुरक्षित न होने से लोगों, पौधों और पशुओं के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहां तक कि पानी के नीचे का जीवन भी ओजोन की कमी से नष्ट हो जाएगा। ओजोन परत कमी से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, सर्दियों की तुलना में अधिक गर्मी होती है, सर्दियां अनियमित रूप से आती हैं और हिमखंड गलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ओजोन परत की कमी स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए खतरा है।

ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक वार्षिक अनुरक्षण है। यह हर साल सोमवार, 16 सितंबर को जागरूकता फैलाने और ओजोन परत की कमी की ओर ध्यान खींचने के लिए मनाया जाता है। इस दिन विश्वव्यापी संगोष्ठी, भाषण और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। स्कूलों में वार्षिक विज्ञान दिवस भी आयोजित किए जाते हैं और मीडिया के जरिए भी जागरूकता फैलाई जाती है। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परिवार, दोस्तों और परिचितों के साथ अपने ग्रह पृथ्वी को अपना योगदान देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। साथ ही विभिन्न अभियान भी शुरू किए गए हैं, जो लोगों की मदद से ओजोन परत की जागरूकता बड़े पैमाने पर फैलाते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे हानिकारक गैसों के उत्पादन और रिहाई को सीमित करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर जोर देता है। चूंकि जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी ओजोन है।

पर्यावरण में ओजोन परत की भूमिका

ओजोन परत तकरीबन 97 से 99 प्रतिशत तक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। इसके संरक्षण को बढ़ावा देने मांट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस वास्तव में पृथ्वी पर सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों के प्रकाश से धरती की रक्षा करने वाली ओजोन परत को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को दोहराने के प्रयास के रूप में प्रतिवर्ष जाता है। पृथ्वी पर पैराबैंगनी किरणों के कुप्रभाव तथा ओजोन परत की जीवनदायनी शक्ति को समझना आवश्यक है। हमारी पृथ्वी पर जीवन, सूर्य द्वारा उपलब्ध करायी ऊर्जा पर ही निर्भर है। सूर्य द्वारा प्रदान की गई कुल ऊर्जा का लगभग आधा भाग ही वास्तव में प्रभावी रूप से पृथ्वी को प्राप्त होता है। इसमें से लगभग तीस प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष शौर्य विकिरण के रूप में तथा शेष बीस प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी से बाहर चला जाता है। ओजोन के अणुओं (ओ-3) में ऑक्सीजन के तीन परमाणु होते हैं। यह जहरीली गैस है और वातावरण में बहुत दुर्लभ है। प्रत्येक 10 मिलियन अणुओं में इसके सिर्फ 3 अणु पाए जाते हैं। 90 प्रतिशत ओजोन वातावरण के ऊपरी हिस्से या समतापमंडल (स्ट्रेटोस्फेयर) में पाई जाती है, जो पृथ्वी से 10 और 50 किमी (6 से 30 मील) ऊपर है । क्षोभमंडल (ट्रोपोस्फेयर) की तली में जमीनी स्तर पर ओजोन हानिकारक प्रदूषक है जो ऑटोमोबइल अपकर्षण और अन्य स्रोतों से पैदा होती है।

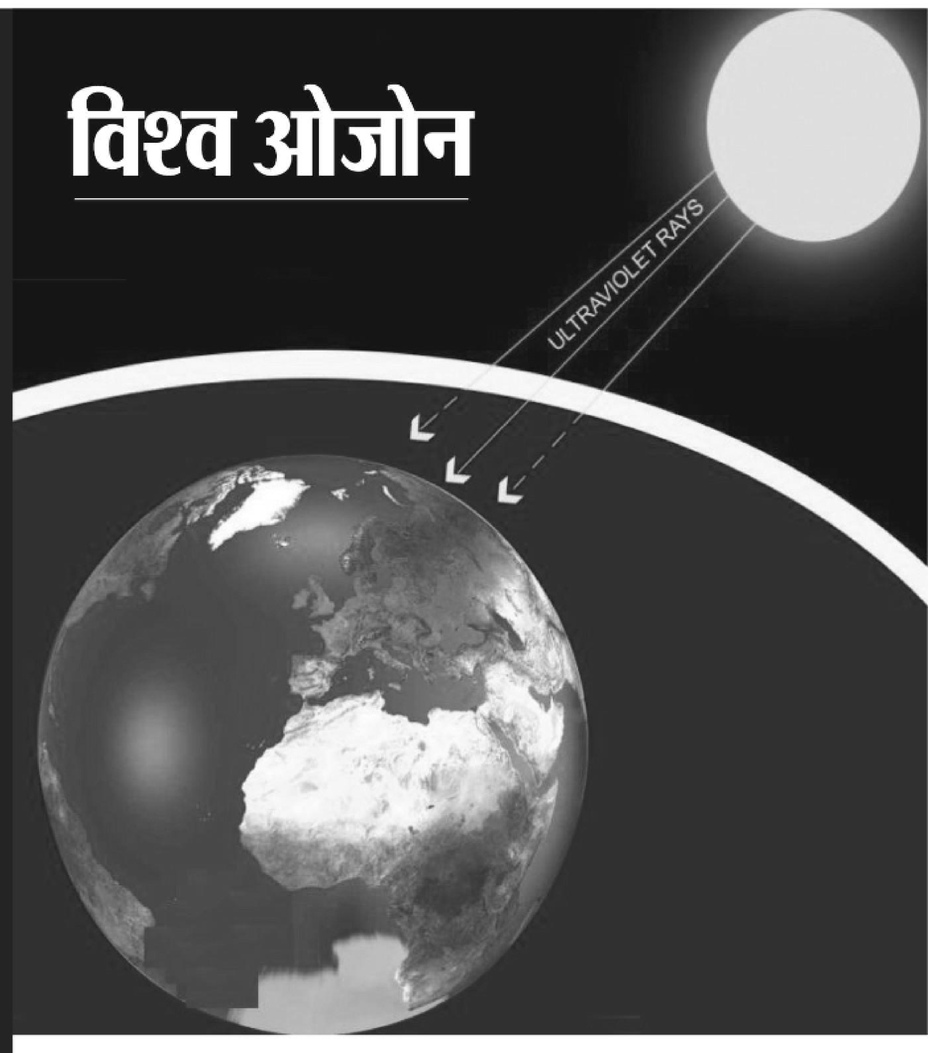

विश्व ओजोन दिवस (वर्ल्ड ओजोन डे) का इतिहास

1994 से 16 सितंबर को सालाना ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सभी देशों में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन को एक घोषणा के रूप में नामित किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया था। 19 दिसंबर 2000 को ओजोन परत की कमी के कारण मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित किया गया था। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन दुनिया भर के हानिकारक पदार्थों और गैसों को समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ओजोन परत की रक्षा के लिए 1995, जो पहला वर्ष था, जब इस दिन को दुनिया भर में मनाया गया था, के बाद से अंतर्राष्ट्रीय दिवस में भागीदारी ने भारी वृद्धि देखी है।

ओजोन-क्षरण के प्रभाव

मनुष्य तथा जीव-जंतुः यह त्वचा-कैंसर की दर बढ़ाकर त्वचा को रूखा, झुर्रियों भरा और असमय बूढ़ा भी कर सकता है। यह मनुष्य तथा जंतुओं में नेत्र-विकार विशेष कर मोतियाबिंद को बढ़ा सकती है। यह मनुष्य तथा जंतुओं की रोगों की लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सकता है।

वनस्पतियांः पराबैंगनी विकिरण वृद्धि पत्तियों का आकार छोटा कर सकती है अंकुरण का समय बढ़ा सकती हैं। यह मक्का, चावल, सोयाबीन, मटर गेहूं, जैसी फसलों से प्राप्त अनाज की मात्रा कम कर सकती है।

खाद्य-शृंखला : पराबैंगनी किरणों के समुद्र सतह के भीतर तक प्रवेश कर जाने से सूक्ष्म जलीय पौधे (फाइटोप्लैकटॉन्स) की वृद्धि धीमी हो सकती है। ये छोटे तैरने वाले उत्पादक समुद्र तथा गीली भूमि की खाद्य-शृंखलाओं की प्रथम कड़ी हैं, साथ ही ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करने में भी योगदान देते हैं। इससे स्थलीय खाद्य-शृंखला भी प्रभावित होगी।

जीवन के लिए क्यों जरूरी है ओजोन?

ओजोन परत के संरक्षण को बढ़ावा देने, और ओजोन के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा 19 दिसंबर 1994 को, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया था, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी वासियों की जीवन रक्षक ढाल के रूप में विद्यमान ओजोन के संरक्षण करना है। यह तारीख पूर्व यूएन महासचिव कोफी अन्नान द्वारा प्रदत्त मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार दिन के रूप में तय की गई थी।

क्या है ओजोन परतः ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप होता है, धरती के वायुमंडल में 35 किमी की ऊंचाई पर 90 से लेकर 120 किमी मोटी ओजोन परत विद्यमान है। जिस प्रकार छाता बारिश से हम को बचाता, ओजोन सूर्य से पृथ्वी को बचाती है।

पराबैंगनी किरणों से बचाती है यह परतः धरती पर उन्नत जीव शृंखला पाए जाने में ओजोन का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वी के वायु मंडल में उपस्थित यह परत सूर्य में होने वाले नाभिकीय संलयन से उत्सर्जित होने वाली अत्यंत हानिकारक/घातक पराबैगनी किरण-3 और-4 को धरती के जीवधारियों तक आने से पहले 99प्रतिशत तक अवशोषित कर लेती है। यह पराबैगनी अल्ट्रावाइलेट(ङ्क) किरणे अत्यंत खतरनाक होती हैं, इनके संपर्क में आने पर त्वचा, नेत्रज्योति, रोगप्रतिरोधक क्षमता में हानिकारक परिवर्तन के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों के होने की पूर्ण संभावना होती है। प्रतिवर्ष बढ़ रहे वैश्विक तापमान और कहीं -कहीं सतरंगी आसमान दिखने की घटना बहुत बड़े खतरे की ओर इंगित करती है, जो ओजोन परत के क्षारण से अवगत कराती है। पृथ्वी पर बढ़ रही मानव आबादी के साथ-साथ घट रही हरियाली, विलुप्त हो रही प्राणियों की प्रजातियों ने हमें शंका में धकेला तो जरूर है, लेकिन हम मनुष्य पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के दंभ में हर बात को नजर अंदाज करते हुए प्रकृति को छेड़ते रहते हैं। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान हमारी विलासिता पूर्ण जिंदगी जीने से हो रहा है।

विश्व ओजोन दिवस (वर्ल्ड ओजोन डे) क्यों मनाया जाता है?

यह दिन न केवल उस तारीख जब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसे याद करने के लिए मनाया जाता है, बल्कि मुख्य रूप से यह जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है कि ओजोन परत कितनी तेजी से कम हो रही है। इस दिन को एक अंतरराष्ट्रीय अवसर के रूप में देखने का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के बारे में जागरूकता की भावना पैदा करना है कि यह कैसे बनती है और इसमें पैदा हुई कमी को रोकने के क्या तरीके हैं। इस दिन विद्यालयों, कॉलेजों, संगठनों और मीडिया के लोगों के जरिए एक दूसरे से जुड़कर उनके विचारों को साझा किया जाता है और यह बताया जाता है कि हमारी धरती को नष्ट करने वाले खतरे को नियंत्रित किया जा सकता है। यह दिवस जनता के बारे में पर्यावरण के महत्व और इसे सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में शिक्षित करता है।

विश्व ओजोन दिवस (वर्ल्ड ओजोन डे) की थीम

ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के वार्षिक उत्सव की अपनी थीम है और यह थीम साल-दर-साल बदलती रहती है। एक साल की थीम को दोबारा दोहराया नहीं जाता और हर साल अधिकारियों द्वारा एक नई और अलग थीम रखी जाती है। ओजोन लेयर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर 2017 को सूर्य के तहत सभी जीवन की देखभाल थीम के साथ मनाया गया था। थीम को इस उद्देश्य पर रखा गया है कि सभी के जीवन का सम्मान करना चाहिए और मनुष्य को निःस्वार्थ रूप से पर्यावरण और वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए काम करना चाहिए ताकि न केवल इंसान बल्कि पौधे और जानवर भी स्वस्थ जीवन जी सकें। पिछले वर्षों की थीम इस प्रकार हैं-

- वर्ष 2019 में ओजोन दिवस के लिए थीम- 32 वर्ष और हीलिंग है
- 2018 की थीम - सूर्य के नीचे जीवन भर की देखभाल।
- 2016 की थीम - ओजोन और जलवायु - विश्व द्वारा पुनर्स्थापित
- 2015 की थीम - 30 साल - हमारी ओजोन का एक साथ इलाज करना
- 2014 की थीम - ओजोन परत संरक्षण - मिशन चल रहा है
- 2013 की थीम - ओजोन दिवस - एक स्वस्थ वातावरण जो हम भविष्य में चाहते हैं
- 2012 की थीम - आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे वातावरण की रक्षा करना
- 2011 की थीम - HCFC फेज़-आउट: एक अनूठा अवसर
- 2010 की थीम - ओजोन परत संरक्षण: शासन और अनुपालन:
- 2009 की थीम - सार्वभौमिक भागीदारी: ओजोन संरक्षण विश्व को एकदम से जोड़ता है
- 2008 की थीम - मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल - वैश्विक लाभ के लिए वैश्विक भागीदारी
- 2007 की थीम - 2007 में 20 साल की प्रगति का जश्न
- 2006 की थीम - ओजोन परत को सुरक्षित रखें, पृथ्वी पर सहेजें जीवन
- 2005 की थीम - ओजोन दोस्ताना अधिनियम - सफर रहें सुरक्षित
- 2004 की थीम - हमारे आकाश को बचाएं: ओजोन फ्रेंडली प्लैनेट, हमारा टारगेट
- 2003 की थीम - हमारे आकाश को बचाएं: हमारे बच्चों के लिए छेद बहुत अधिक है
- 2002 की थीम - हमारे आकाश को बचाएं: खुद को सुरक्षित रखें; ओजोन परत की रक्षा करें

इन गैसों से हो रहा है ओजोन को नुकसान

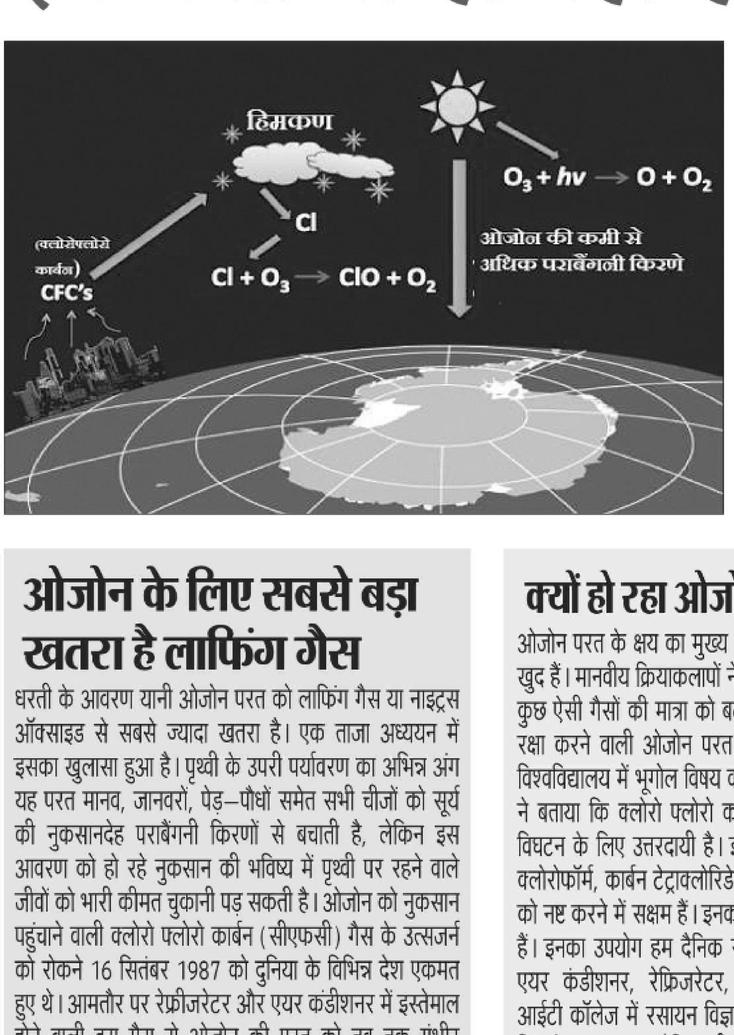

कार्बन डाई ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, अमोनिया, मीथेन जैसी गैसें वातावरण के साथ ही ओजोन की परत को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। 1994 में हुए एक शोध से ज्ञात हुआ था कि 1930 के आस-पास से ही ओजोन परत का ह्रास होना शुरू हो गया था, जो निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले अंटार्कटिका महाद्वीप के आसमान की ओजोन में बहुत बड़ा छेद देखा गया था, फिर ऑस्ट्रेलिया में रंगीन आसमान देखा गया था, जहां से ओजोन परत गायब थी। ओजोन परत के ह्रास में हानिकारक गैसों और पेड़ों की कमी के साथ दूसरा सबसे बड़ा कारण सुपरसोनिक विमानों के द्वारा छोड़े गए नाइट्रस ऑक्साइड जो ओजोन को रासायनिक अभिक्रिया से ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं, दूसरा परमाणु परीक्षण है, प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे तत्वों के विकिरण बेहद खतरनाक होते हैं, जिनसे ओजोन का अवशोषण बड़ी मात्रा में हो जाता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन बड़ी मात्रा में होने से उस क्षेत्र के ओजोन की मूल संरचना में परिवर्तन हो जाता है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया भर के देशों से ओजोन के संरक्षण के लिए प्रयास करने को कह रहा है। यूएन का कहना है कि यदि पर्यावरण के प्रति हम जिम्मेदार नहीं हुए तो, परिणाम बहुत विनाशक होगा?

कैसे मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस ?

1994 से ओजोन परत की कमी के परिणाम के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाने तथा इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व ओजोन दिवस (वर्ल्ड ओजोन डे) मनाया जाता है। इस दिन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयासों के साझा, जो मुख्यतः पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनते हैं, को प्रोत्साहित किया जाता है। ये लोग दूसरों को जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों में शामिल होने और इस अंतर्राष्ट्रीय अवसर के जश्न के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का विस्तार करने के लिए प्रेरित करते हैं। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता इस दिवस के फायदों को फैलाने जागरूकता रैलियां करते हैं। इस मुद्दे पर मीडिया ने कई स्वयंसेवक कार्यक्रमों को ऑनलाइन आयोजित करने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों में योगदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि लोगों को शिक्षित करने के लिए इस मुद्दे के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री वितरित कर सकें। ओजोन परत के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम को बढ़ावा देने के लिए आजकल युवाओं ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया साइटों का उपयोग शुरू किया है। वे अपने क्षेत्र में घटनाओं, प्रसिद्ध पर्यावरण उद्धरण और तथ्यों को साझा करते हैं। युवा वर्ग उस वर्ष की विशेष थीम के आधार पर चित्रकारी करते हैं और ओजोन की कमी और उसके नतीजों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर ऑनलाइन भाषण देते हैं। ओजोन पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जश्न अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह से मनाया जाता है।

भारत

ओजोन परत के संरक्षण के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस छात्रों द्वारा उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन सड़कों पर रैलियां की जाती हैं, छात्रों को वार्षिक ओजोन दिवस पर भाषण देने का मौका दिया जाता है। महाविद्यालय के छात्र इस विषय पर राज्य स्तर के अभियान आयोजित करते हैं और इस तरह से ओजोन परत में छेद को कम करने के लिए विभिन्न उपाय इस्तेमाल में लाते हैं। भारतीय सरकार उन बुद्धिमान लोगों को मान्यता और छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जो हानिकारक गैसों और पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने रचनात्मक तरीकों का आविष्कार करते हैं, जो न सिर्फ सुविधाजनक बल्कि स्थायी भी है। पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ कार्यक्रमों को लॉन्च करने और मानव जाति के लिए वातावरण में मौजूद हानिकारक गैसों के आंकड़ों को इकट्ठा किया, जिनका बुरा प्रभाव धरती पर पड़ रहा है। ये अद्यतन आंकड़े विभिन्न विश्वविद्यालयों को व्यापक रूप से अध्ययन करने और इस मुद्दे पर पर्याप्त समाधान प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं।

ऑस्ट्रेलिया

अन्य देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भाग लेकर ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। छोटे समूहों के रूप में राष्ट्र के युवा लोगों से संपर्क करते हैं और उनसे बात करते हैं। युवा उन्हें बताते हैं कि हमारी लापरवाही से पर्यावरण को कीमत चुकानी पड़ रही है तथा कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की आशा को भी प्रज्वलित करते हैं। दिन रोजमर्रा गतिविधियों से भरा है। छात्रों को आम तौर पर अपने संस्थानों में निबंध, पैराग्राफ या लेख लिखने के लिए विषय मिलते हैं, ताकि शिक्षकों को यह समझ आए कि वे इस तकनीकी दुनिया में पर्यावरण के प्रति कितने गंभीर हैं। थीम पर आधारित क्षेत्रीय गतिविधियों को सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, ताकि जागरूकता फैल सके।

यूरोप

यूरोप एक बड़ा महाद्वीप है और यही कारण है कि इस महाद्वीप का योगदान जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण में अधिक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पर संपूर्ण विश्व के लोगों को इस लड़ाई में शामिल होने के लिए वास्तविक वातावरण स्थितियों से अवगत कराने और ओजोन के खिलाफ एक प्रभावी कार्यक्रम में भागीदार होने का निवेदन करता है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के जरिए इस उत्सव को मनाया जाता है, ताकि इस खतरे के बारे में सभी को चेताया जा सके, जिसने जलवायु परिस्थितियों में काफी समस्या पैदा की है।

अफ्रीका

अफ्रीका में विश्व ओजोन दिवस को विभिन्न गतिविधियों के रूप में मनाया जाता है। इन गतिविधियों में पर्यावरणीय संकटों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए लोगों द्वारा अकादमिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में आयोजित होने वाली घटनाएं शामिल हैं। विभिन्न पर्यावरण अनुसंधान समितियों के स्वयंसेवक और कर्मचारी आम लोगों को ओजोन परत की कमी के बारे में बताते हैं, ताकि इससे धन जुटाया जा सके और उस धन को उन आविष्कारों में वितरित कर सकें, जो हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।

ओजोन के लिए सबसे बड़ा खतरा है लाफिंग गैस

धरती के आवरण यानी ओजोन परत को लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड से सबसे ज्यादा खतरा है। एक ताजा अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है। पृथ्वी के उपरी पर्यावरण का अभिन्न अंग यह परत मानव, जानवरों, पेड़-पौधों समेत सभी चीजों को सूर्य की नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों से बचाती है, लेकिन इस आवरण को हो रहे नुकसान की भविष्य में पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सीएफसी) गैस के उत्सर्जन को रोकने 16 सितंबर 1987 को दुनिया के विभिन्न देश एकमत हुए थे। आमतौर पर रेफ्रीजरेटर और एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होने वाली इस गैस से ओजोन की परत को तब तक गंभीर नुकसान होना शुरू हो चुका था। सीएफसी पर पाबंदी लगने के बाद इसके उत्सर्जन में खासी कमी आई थी और ओजोन की परत में सुधार हुआ था, किंतु हर साल एक करोड़ टन नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होने से हालात फिर खराब हो सकते हैं। यह गैस इस वक्त ओजोन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है

क्यों हो रहा ओजोन परत का क्षय?

ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण कुछ और नहीं बल्कि हम खुद हैं। मानवीय क्रियाकलापों ने अज्ञानता के चलते वायमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है, जो धरती पर जीवन रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे निशांत शर्मा ने बताया कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन परत में होने वाले विघटन के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोरिडे आदि रसायन पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में सक्षम हैं। इनको हम ओजोन क्षरण पदार्थ कहते हैं। इनका उपयोग हम दैनिक सुख सुविधाओ में करते हैं जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक आदि। आईटी कॉलेज में रसायन विज्ञान की एमएससी की छात्रा श्रुति सिंह के अनुसार हम दैनिक जीवन में बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग करते हैं, जिनमें कोई न कोई गैस का रिसाव होता है। इनमें एयर कंडीशनर है, जिसमें प्रयुक्त गैस फ्रियान-11, फ्रियान-12 है। यह ओजन के लिए हानिकारक है, इन गैसों का एक अणु ओजोन के लाखों अणुओं को नष्ट करने में सक्षम है।

ओजोन परत संरक्षण के लिए विश्वस्तरीय प्रयास

ओजोन-क्षय विषयों से निबटने अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए अंतर-सरकारी बातचीत 1981 में प्रारंभ हुई। मार्च, 1985 में ओजोन परत के बचाव के लिए वियना में एक विश्वस्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ओजोन संरक्षण से संबंधित अनुसंधान पर अंतर-सरकारी सहयोग, ओजोन परत के सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण, सीएफसी उत्पादन की निगरानी और सूचनाओं के आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर वार्ता की गई। 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कनाडा के मांट्रियाल शहर में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे मांट्रियाल प्रोटोकाल कहा जाता है। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ जैसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सीएफसी) के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाए। भारत ने भी इस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए। 1990 में मांट्रियल संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने 2000 तक सीएफसी और टेट्रा क्लोराइड जैसी गैसों के प्रयोग पर भी पूरी तरह से बंद करने की शुरुआत की।

लंबे समय तक किया इंतजार, विशेष कानून लाकर राम मंदिर का निर्माण कराए सरकार: शिवसेना

■ मुंबई/ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में रोजाना सुनवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत और बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को विशेष कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, फैसला कभी भी आ सकता है इसलिए शिवसैनिक राम मंदिर की पहली ईंट रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का साहसिक निर्णय लिया है, उसी तर्ज पर मोदी सरकार को राम मंदिर पर एक विशेष कानून बनाकर साहसिक निर्णय लेना चाहिए। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि हमने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है अब और समय नहीं गंवाना चाहिए।

दादरी पुलिस ने 1000 पेटी तस्करी की शराब बरामद की, ट्रक चालक गिरफ्तार

नोएडा/ब्यूरो

थाना दादरी पुलिस ने सोमवार को एक ट्रक में भरकर ले जाई जा रही 1,000 पेटी तस्करी की शराब बरामद की है। गौतम बुध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि सोमवार को एक सूचना के आधार पर थाना दादरी पुलिस ने लोहारली टोल प्लाजा के पास एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें एक हजार पेटी हरियाणा मार्का शराब मिली। उन्होंने बताया कि ट्रक चला रहे अनिल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बरामद शराब की कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह काफी दिनों से शराब तस्करी के धंधे में संलिप्त है।

स्मार्ट सिटी नहीं जनाब अतिक्रमण स्मार्ट सिटी कहिए

...दुर्भाग्य देखिये। अतिक्रमण होना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अतिक्रमण हटाना आज शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है। सुंदर शहर की सूरत को अतिक्रमण ने पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है।

शहर में अतिक्रमणकारियों के बढ़ते दबदबा को कम करने की दिशा में प्रशासन की उदासीनता भारी साबित हो रही है। अब इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आम लोगों को सड़क जाम से निजात दिलाने की दिशा में वातायात पुलिस और नगर निगम के पदाधिकारियों का आश्वासन अब खलने लगा है। शहरी क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराने में प्रशासन आगे क्यों नहीं आता है?

क्या शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराना उनके बूते से बाहर की बात हो गई है या फिर अतिक्रमणकारियों के समक्ष सिस्टम लाचार हो चुका है? ऐसे कई सवाल उठने लगे हैं। लाजिमी है, क्योंकि कार्रवाई के अगले दिन ही सड़कों पर दुकानें सजने लगती हैं। उनकी तो जेबें गरम होती हैं पर आम इंसान की जेबें खाली हो रही हैं। घंटों जाम में फंसने से उनकी गाढ़ी कमाई धुएं में उड़ रही है। शहर के लगभग सभी फुटपाथ पर दुकानें सजी हैं। जब भी हाईकोर्ट का चाबुक चलता है तो शहर में अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। निर्देश के बाद पूरे शहर से आनन-फानन सड़क किनारे फुटपाथी दुकानदारों का हटाया जाता है। लेकिन इसके दूसरे ही दिन सड़क किनारे हटाए गए कुछ फुटपाथियों द्वारा फिर अपना कब्जा जमा लिया जाता है। स्वाभाविक है जिला व नगर निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण ही शहर में अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ा है।

-विजय कुमार

अकालियों पर बरसे अमरिंदर सिंह, एसजीपीसी को बताया अकाली दल के हाथों का खिलौना

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को एक बार फिर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को ''कम समझ वाली महिला'' बताया और उनसे कहा कि ''तुच्छ राजनीतिक लाभों'' के लिए वह गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के मुद्दे का ''फायदा उठाना'' बंद करें। मुख्यमंत्री ने एसजीपीसी को शिरोमणी अकाली दल के हाथों का ''खिलौना'' बताया और आरोप लगाया कि सरकार और धार्मिक संगठन के बीच खाई को गहरी करने की हरसिमरत हर संभव कोशिश कर रही हैं।

इससे पहले बीते मंगलवार को भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने हरसिमरत को ''कम समझ वाली महिला'' बताया। दरअसल कौर ने आरोप लगाया था कि सरकार सिख धर्म के संस्थापक के जयंती समारोह पर राजनीति कर रही है, जिसके जवाब में सिंह ने यह कहा। कौर ने कहा था कि राज्य सरकार अकाल तख्त को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

मुख्यमंत्री ने एक वक्तव्य में कहा कि कौर आधारहीन आरोप लगाकर उनकी सरकार की छवि खराब करने के लगातार प्रयास कर रही हैं और यह सब ''एक कम समझ वाली महिला'' के झूठ हैं।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक वक्तव्य में कहा कि कौर आधारहीन आरोप लगाकर उनकी सरकार की छवि खराब करने के लगातार प्रयास कर रही हैं और यह सब ''एक कम समझ वाली महिला'' के झूठ हैं।

'राष्ट्रभक्त' फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए का इस्तेमाल अनुचित: कांग्रेस

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए जाने की निंदा करते हुए सोमवार को कहा कि एक 'राष्ट्रभक्त' नेता के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि भारत की एकता एवं अखंडता की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को जेल में डाला जा रहा है।

आजाद ने संवाददाताओं से कहा, ''मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। यह देश का दुर्भाग्य है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मुख्याधारा की पार्टी के नेता के साथ यह हुआ है।'' उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी है और उसने देश की एकता एवं अखंडता के लिए काम किया है। आजाद ने कहा, ''जम्मू-कश्मीर में अगर आतंकवाद नहीं है तो वह जम्मू-कश्मीर की जनता, कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के कारण हुआ है। भाजपा के कारण यह नहीं हुआ है।''

कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा, ''मुझे लगता है कि ये फारूक साहब के साथ अन्याय है।

वह हमेशा से एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति रहे हैं। आप उनके भाषण उठाकर देख सकते हैं। उनके पुत्र (अटल बिहारी) वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं। वह कई सरकारों में रहे हैं। उनके लिए इस तरह के कानून का इस्तेमाल उचित नहीं है।

उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए भी सरकार का ये कदम उचित नहीं है।'' गौरतलब है कि अब्दुल्ला को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। पीएसए के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि भारत की एकता एवं अखंडता की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को जेल में डाला जा रहा है।

पाकिस्तान अपने ही 'आतंकवाद के दानव' से तबाह हो जाएगा: मुख्तार अब्बास नकवी

■ रामपुर/ब्यूरो

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान अपने ही 'आतंकवाद के दानव' से बर्बाद हो जाएगा जिसे उसने अपनी धरती पर बढ़ावा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय एकता अभियान के दौरान रामपुर में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि हताश पाकिस्तान, उसके आतंकवादी दोस्त और खुफिया एजेंसी आईएसआई अब भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन आतंक के इन आकाओं को समझ लेना चाहिए कि भारत में अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों की शैतानी हरकतें और जड़ें नहीं जम पाई हैं, इसमें भारत के मुसलमानों की राष्ट्रवादी सोच का बड़ा योगदान है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों ने हमेशा आतंकवाद को ठुकराया है और अमन और इंसानियत का साथ दिया है। उनके कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीं पर आतंकवाद के जिन दानवों को पाला पोसा है, उसी से वह तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने नापाक इरादों के कारण दुनिया में अलग-थलग हो चुका पाकिस्तान 'इस्लाम खतरे में है' के पाखंडी नारे से अपनी आतंकी फैक्टरी पर परदा डालना चाहता है। नकवी ने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की शांति और इंसानियत के लिए खतरा है। जिस बात को भारत ने बहुत पहले समझ लिया था, उसे आज पूरी दुनिया जान चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परस्त अलगाववादी-आतंकवादी अनुच्छेद 370 को अपना हथियार बना कर जम्मू, कश्मीर, लद्दाख के लोगों की प्रगति और शांति में खलल डाल रहे थे। अब उस ''हथियार'' को तोड़ दिया गया है। नकवी ने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू, कश्मीर, लद्दाख के लोगों की खुशहाली सुनिश्चित होगी। इसी वजह से पाकिस्तान, आतंकवादी, अलगाववादी बौखला गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मूवमेंट

क्या नशे में डूब चुके लाखों युवाओं की जिंदगियां बचा पाना संभव ?

■ जालंधर से नीरज की विशेष रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही गत दिनों फिट इंडिया मूवमेंट की जोर-शोर से शुरुआत की है लेकिन इसकी राह में नशा और मानसिक तनाव आड़े आ रहा है। पंजाब की युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा चिट्टे, हेरोइन, स्मैक व नशीली दवाइयों की पकड़ में आ चुका है। पहले पुरुष व युवा वर्ग नशे की चपेट में था और अब कई लड़कियां भी इस जानलेवा नशे की गिरफ्त में आने लगी हैं। एक जानकारी के अनुसार पंजाब के कई कस्बों, गांवों व परिवारों में नशीले पदार्थ बेचने में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं और नशे की डिलीवरी का काम आसान हो गया है।

नशे की चपेट में आकर युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके अलावा, मानसिक तनाव, बिगड़ी दिनचर्या, काम की समयावधि लंबी होना भी कुछ ऐसे कारण हैं, जो लोगों की सेहत को बिगाड़ रहे हैं। दवाओं पर लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। पंजाब की मौजूदा कांग्रेस सरकार की ओर से जहां इसे लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं जागरूकता का अभाव भी फिटनेस में बाधा बना हुआ है। चिकित्सकों की मानें, तो युवा अवस्था में बीमारियां घेरने लगी हैं, जबकि इनसे बचने के लिए थोड़ा लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। सरकारी व निजी अस्पतालों की ओपीडी की बात की जाए तो दिन-प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या ऐसे मरीजों की है जो गलत खानपान और जीवनशैली से प्रभावित होते हैं। फिलहाल, केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान से पंजाब में एक उम्मीद बंधती दिखाई देती है। यदि इस अभियान को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाना है तो पहले इनकी राह में आने वाली बाधाओं से पार पाना होगा। नशे में डूब चुके इन लोगों को बचाने के लिए जब तक पंजाब सरकार भी फिट इंडिया अभियान के साथ ईमानदारी से काम नहीं करती, तब तक नशे में डूब चुके लाखों युवाओं की जिंदगियां बचा पाना संभव नहीं है। अगर पंजाब के इन लाखों युवाओं की जिंदगियां बचानी हैं तो पंजाब के सभी सामाजिक, धार्मिक व शिक्षण आदि संगठनों, एन.जी.ओ. को आम जनता को साथ लेकर चलना होगा।

विलेन न बन जाए नशा, मानसिक तनाव बिगाड़ रहा सेहत, युवा भी तेजी से आ रहे चपेट में

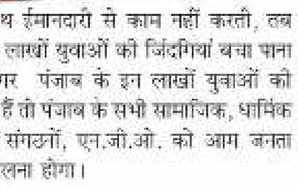

मंत्रीमंडल द्वारा एस.सी. कमीशन के चेयरपर्सन की आयु सीमा बढ़ाकर 72 साल तक करने की मंजूरी

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा पंजाब स्टेट कमीशन फॉर शड्युल कास्टस एक्ट, 2004 में संशोधन करते हुए चेयरमैन की आयु सीमा 70 से बढ़ाकर 72 साल करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के उपरांत सरकारी प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब स्टेट कमीशन फॉर शड्युल कास्टस एक्ट, 2004 की धारा 4(1) में संशोधन के लिए एक ऑर्डीनेंस लाया जायेगा। इस समय पर चेयरपर्सन के सेवाकाल की सीमा छह साल या 70 साल उम्र है, जिनमें से जो भी पहले आए।

मंत्रीमंडल द्वारा किया यह फैसला पद के लिए और ज्यादा तजुर्बेकार व्यक्ति लगाने में सहायता करेगा और राज्य में एस.सी. भाईचारे के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए बने कानूनों को असरदार तरीके से लागू करने में अहम योगदान डालेगा। अनुसूचित जातियों के लिए पंजाब राज्य आयोग का गठन द पंजाब स्टेट कमिशनर शड्युल कास्टस कमीशन एक्ट, 2004% के अंतर्गत किया गया था।

आयोग के चेयरपर्सन की नियुक्ति के सम्बन्ध में 2004 के कानून की धारा 3(2) (ए) के अनुसार सरकार द्वारा चेयरपर्सन की नियुक्ति, अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित प्रसिद्ध शख्सियत या फिर अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित राज्य सरकार का सेवा मुक्त अधिकारी जो कम से कम प्रमुख सचिव के पद पर रहा हो, में से की जाती है।

पंजाब सरकार द्वारा खाली पदों को भरने के लिए सिविल सेवाओं के भर्ती नियमों को आसान बनाने का फैसला

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब सरकार ने विभिन्न कानूनों में संशोधन करके राज्य में योग्य सिविल सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों को आसान बनाने का फैसला किया है जिससे उचित उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली पड़े पदों को भरने के लिए रास्ता साफ होगा।

इस संबंधी फैसले का ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के बाद किया गया जो पंजाब राज्य सिविल सेवाओं को साझी परीक्षा के आधार पर सेवाओं की विभाजन के साथ जुड़े मुद्दों को सुलझाने में सहायक होगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने परसोनल विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके अंतर्गत पंजाब रिकरुटमैंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन के रूल 4(2), पंजाब रिकरुटमैंट ऑफ स्पोर्टसमैन रूल्ज-1998, पंजाब स्टेट सिविल सर्विसज (अपायंटमैंट बाय कम्बाईनड ऐगजामीनेशन) रूल्ज, 2009 के मसौदे के नोटीफिकेशनों में अपेक्षित संशोधन करने के अलावा पंजाब स्टेट सिविल सर्विसज (अपायंटमैंट बाय कम्बाईनड ऐगजामीनेशन) रूल्ज, 2009 में रूल 10 (ए) जोड़ना शामिल है।

प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने इन रूलों के अंतिम मसौदे की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। यह जिक्रयोग्य है कि पंजाब सिविल सांझे सेवाओं मुकाबले भर्ती परीक्षा -2018 के बाद में पंजाब लोक सेवा आयोग सरकार द्वारा प्रकाशित की गई 72 पदों के विरुद्ध विभाजन करने के लिए उम्मीदवारों की मेरिट सूचियां भेजी थी जिसमें पंजाब सिविल सेवाओं (कार्यकारी शाखा), उप पुलिस कप्तान, आबकारी और कर अफ़सर, तहसीलदार, खाद्य सप्लाई अफसर, ब्लॉक विकास और पंचायत अफ़सर, लेबर -कम -कौनसीलेशन अफसर और रोजगार सृजन और प्रशिक्षण अफसर के पद शामिल हैं। इनमें से 17 आरक्षित पदों के लिए उम्मीदवार न मिलने के कारण पद खाली पड़े हैं जिसके बाद पंजाब लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को इन पदों को भरने के लिए उपयुक्त फ़ैसला लेने की विनती की थी। सरकार को बताया गया कि पिछले समय में भी ऐसी स्थितियां पैदा होती रही हैं क्योंकि ऐसी स्थितियों के साथ निपटने संबंधी नियम /हिदायतें स्पष्ट नहीं थी।

मौजूदा नियमों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के पद खाली हैं जिनमें आरक्षित अनुसूचित जातियों, वाल्मीकि और मजबी सिख और आम श्रेणी और एक्स-सर्विसमैन श्रेणियां शामिल हैं जिनको विभिन्न तौर पर विचारा जाता रहा। इस कारण यह अस्पष्टता बनी रही कि वाल्मीकि और मजबी सिख श्रेणी से एक्स-सर्विसमैन और खेल कोटे की खाली पड़े पदों को वाल्मीकि और मजबी सिख के जनरल पूल या सभी अनुसूचित जातियों के जनरल पूल में से भरा जाए।

ऐसी स्थिति में इन पदों को भरने सम्बन्धी मुकदमेबाजी लम्बा समय चलती थी। इन हालतों के मद्देनजर परसोनल विभाग ने प्रसावित किया कि नियमों और हिदायतों में संशोधन करके सभी श्रेणियों के पदों के लिए स्पष्ट, न्यायपूर्वक और स्थिरता बनाई जाये और इसके साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के हितों की सुरक्षा को भी यकीनी बनाया जाये।

जन्मदिन के मौके पर नर्मदा बांध का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

■ अहमदाबाद/ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 69 वर्ष के होने जा रहे हैं और इस मौके पर वह नर्मदा नदी पर बने गुजरात के सरदार सरोवर बांध स्थल पर जाएंगे जहां जल पहली बार सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। बांध का जलस्तर 2017 में पहली बार बढ़ाया गया था।

उसके बाद से जलस्तर रविवार शाम को 138.68 मीटर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।

राज्य सरकार द्वारा सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री सोमवार रात को अहमदाबाद हवाईअड्डे पर उतरेंगे। वह मंगलवार सुबह अपने 69वें जन्मदिन के अवसर पर नर्मदा जिले के केवड़िया में बांध स्थल का दौरा करेंगे और जल सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए आयोजित 'नमामि देवी नर्मदे महोत्सव' में शामिल होंगे।